

## शहर: काकीनाड़ा

## राज्य: आंध्र प्रदेश

श्रेणी: पोर्ट सिटी, टायर 3 और इससे नीचे

काकीनाड़ा आन्ध्र प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा शहर है जो प्रमुख क्षेत्रीय नदी गोदावरी के मुहाने से सटा है। शहर में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एवं पीपीपी पहल के रूप में बनाया गया देश का पहला बंदरगाह है। इसी प्रकार की एक अन्य प्रणाली के माध्यम से शहर में एक नया शिपयार्ड स्थापित किया जा रहा है। शहर प्रमुख तौर पर सी फूड एवं उर्वरक का निर्यात करता है।

### 1. जनसांख्यिकी प्रोफाइल

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
कुल जनसंख्या	312538	14610410	377,106,125
यूए की कुल जनसंख्या (यदि)	443028		
जिला शहरी आबादी में यूएलबी आबादी की हिस्सेदारी (%)	23.79		
जनसंख्या वृद्धि दर (एईजीआर) 2001-11	0.53	2.88	2.76
क्षेत्र (वर्ग मीटर)*	57.36		
जिले में यूएलबी क्षेत्र का हिस्सा (%)*	0.53		
जनसंख्या का घनत्व (व्यक्ति वर्ग प्रति किमी)*	5449		
साक्षरता दर (%)	80.62	79.17	84.11
अनुसूचित जाति (%)	8.70	11.60	12.60
अनुसूचित जनजाति (%)	0.54	2.31	2.77

युवा, 15-24 वर्ष (%)	20.55	19.95	19.68
स्लम जनसंख्या (%)	35.85	7.57	17.36
कार्य आयु समूह, 15-59 वर्ष (%)	68.13	66.06	65.27

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011

\*जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना, 2011

## 2. आर्थिक प्रोफाइल

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
2004-05 के स्थायी कीमत पर प्रति व्यक्ति आय (रु.)*	37712	33350	रु. 35,947 <sup>a</sup>
शहरी गरीबी का अनुपात (शहरी आबादी का %)**	4.64	8.1	13.7
बेरोजगारी दर, 2011-12***	4.94	2.9	3.4
कार्य करने वालों की दर, 2011-12***	37.07	38.2	35.5
कार्य की स्थिति, 2011-12 (प्रतिशत)***			
स्व नियोजित:			
नियमित/मजदूरी वेतनभोगी कर्मचारी:	45.37	40.1	42.0
	43.85	40.1	43.4
अनौपचारिक श्रम।	10.78	19.8	14.6
मजदूरों का क्षेत्रवार वितरण, 2011-12 (प्रतिशत)***			
प्राथमिक	9.69	8.7	7.5
द्वितीय	28.06	29.8	34.2
तृतीयक	62.25	61.5	58.3

प्रमुख व्यवसायों द्वारा मजदूरों का वर्गीकरण, 2011-12 प्रतिशत)***	17.78	12.7	15.8
व्यवस्थापक, वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंधक	9.95	6.5	8.8
व्यवसाय	5.60	7.1	6.7
तकनीशियनों और एसोसिएट पेशेवर	5.85	4.5	5.0
क्लर्क	10.31	15.2	14.7
सेवा श्रमिक और दुकान एवं मार्केट सेल्स श्रमिक	5.06	4.4	4.6
कुशल कृषि एवं मत्स्य श्रमिक	18.47	21.6	19.2
शिल्प और संबंधित ट्रेडों के श्रमिक	9.62	9.8	9.2
प्लांट और मशीन ऑपरेटरों और संयोजनकर्ता (अस्सेम्ब्लेर्स)	17.37	18.5	16.1
एलिमेंटरी व्यवसाय	0	0	0.1
श्रमिक कब्जे से वर्गीकृत नहीं			
प्राथमिक वस्तु निर्माता#	दुग्ध उत्पाद रिफाइंड तेल उर्वरक		
प्रमुख उद्योग##	स्टील उद्योग जैव ईंधन पेपर मिल		
स्वीकृत एसईजेड की संख्या	4	35	413

नोट: 2007-08, 2008-09 और 2009-10 का 3 वर्ष औसत

स्रोत: \*सभी भारत- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय

\*\*राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की यूनिट लेबल डाटा, भारत में घरेलू उपभोक्ता व्यय, 68<sup>वां</sup> राउंड, 2011-12

\*\*\*राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की इकाई स्तर डेटा, भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति, 68<sup>वां</sup> राउंड, 2011-12

#जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना, 2011

##जिला औद्योगिक प्रोफाइल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, भारत सरकार

∞ वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

### 3. अवसंरचना स्थिति

संकेतक	शहर (डिनोमिनेशन)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
घर के अंदर नल के पानी का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत (बनाये गए स्रोतों से)	83.29	71.52	84.14
बिजली के उपयोग के साथ घरों का %	97.40	97.29	92.68
घर के अंदर शौचालय की सुविधा वाले परिवारों का %	82.63	79.44	72.57
गंदे पानी के माध्यमों का ड्रेनेज से जुड़े परिवारों का प्रतिशत	84.14	85.38	81.77
सीवरेज प्रणाली का प्रकार*	भूमिगत सीवरेज प्रणाली		
ठोस अपशिष्ट प्रणाली का प्रकार*	द्वार से द्वार		
कम्प्यूटर/लैपटॉप का इंटरनेट के उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत	6.08	4.25	8.27
कम्प्यूटर/लैपटॉप का बिना इंटरनेट के उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत	9.39	7.81	10.40
मोबाइल फोन के उपयोग के साथ घरों का %	57.46	62.68	64.33
आवास का स्वामित्व पैटर्न (%)			
स्वामित्व	52.66	53.15	69.16
किराए पर	45.83	45.05	27.55
भीड़भाड़ वाले घरों में रहने वाले परिवारों का %	31.21	36.34	32.94

संकेतक	शहर (डिनोमिनेशन)
प्रति 1,00,000 लोगों पर अस्पतालों की संख्या*	0.3
प्रति 1,00,000 लोगों पर स्कूलों की संख्या*	
प्राथमिक	65
माध्यमिक	42
द्वितीयक	27
महाविद्यालय	9

स्रोत: मकान, घरेलू सुविधाएं और परिसंपत्तियों की तालिका, भारत की जनगणना, 2011

\*जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना, 2011

#### **4. राजनीतिक प्रोफाइल: नेतृत्व और प्रशासनिक ढांचा**

<p><u>शासन की वास्तुकला</u> चुने गए एवं कार्यकारी निकायों की संरचना। पदानुक्रम के संकेत दें।</p>	<p>शहर में दो क्षेत्र हैं और पुल के द्वारा जुड़े हुए हैं। दक्षिणी हिस्सा, जगन्नाथपुरम बकिधंम नहर के द्वारा शहर के बाकी हिस्सों से अलग है। काकीनाड़ा का उत्तरी क्षेत्र अपने हाल के विस्तार के साथ शहर का अधिक आधुनिक हिस्सा है। काकीनाड़ा नगर निगम शहर को नियंत्रित करता है। निगम जिला कलेक्टर एवं विशेष अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में होता है। उसके अधीनस्थ नगर निगम आयुक्त है जिसको एक अतिरिक्त आयुक्त एवं उपायुक्त द्वारा समर्थित होता है। सचिव निर्वाचित प्रधान होता है जो पार्षदों की अध्यक्षता करता है। काकीनाड़ा नगर निगम 50 वार्डों में बटा हुआ है।</p> <p>नगर निगम कर (पानी, भूमि, संपत्ति आदि) इकट्ठा, शहर के ठोस अपशिष्ट, इमारतों को बनाने की मंजूरी एवं इनका मूल्यांकन, नगर पालिका विद्यालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र आदि का प्रबंधन करते हैं। ये सड़क, नालों को बनाते हैं एवं इनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले परिवारों को पानी के कनेक्शन भी उपलब्ध कराते हैं।</p>
--	--

	<p>आन्ध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड (एपीएचबी) पिछले नगर सुधार मंडल एवं दोनों शहरों के टाउन इंप्रूवमेन्ट ट्रस्ट को मिलाकर बनाया गया है जो एक सस्ती कीमत पर जरूरतमंद नागरिकों को रहने के लिए आवास प्रदान करने में संलिप्त हैं। ये संयुक्त/एकीकृत आवास योजनाओं के निर्माण, दुकानों के निर्माण, व्यावसायिक परिसरों एवं बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में भी लगे हुए हैं। वर्तमान में एएचबीपी काकीनाड़ा में स्व वित्त योजना के तहत एकीकृत आवास योजना (आवास जो सभी वर्गों एवं आय समूह के लिए) लेने के लिए इच्छुक है।</p> <p>आन्ध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एपीपीसीबी) आन्ध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्राधिकार के अंदर पर्यावरण के कानून एवं नियमों को लागू करने के लिए अधिकृत है। बोर्ड हैदराबाद के अपने मुख्य कार्यालय एवं काकीनाड़ा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से कार्य करता है।</p>
निर्वाचित प्रतिनिधियों की सं.	लागू नहीं
<p><u>निर्वाचन विवरण*</u></p> <p><i>चुनाव चक्र, पिछला चुनाव, नाम, जहां प्रासंगिक हो पार्टी की संबद्धता, मुख्य मंत्री, आयुक्त एवं महापौर के लिए कार्यालय ग्रहण करने की तारीख।</i></p>	<p>तेलुगू देशम पार्टी से श्री चन्द्र बाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें 8/6/2014 को निर्वाचित किया गया था। आयुक्त श्री प्रवीण कुमार है।</p>

स्रोत: \*संबंधित यूएलबी वेबसाइट और मीडिया सर्च

## 5. शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) का कार्यनिष्पादन

### क्रेडिट और कर

शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग (नवम्बर 2012 तक)* लागू नहीं	
संपत्ति कर#	<p>कवरेज (%): लागू नहीं</p> <p>संग्रह क्षमता (%): 95% से ऊपर</p> <p>राशि (रु.): 33.57 करोड़ (2014-15)</p>

स्रोत: \*www.jnnurm.nic.in

#रिफॉर्म मूल्यांकन रिपोर्ट, जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

**शहरी स्थानीय निकायों में ई-गवर्नेन्स एवं कम्प्यूटरीकरण**

सुधार	स्थिति (कार्यान्वित, प्रगति में और किसी भी टिप्पणी में)
संपत्ति कर*	
लेखांकन*	
जल आपूर्ति और अन्य सुविधाएं*	
जन्म और मृत्यु पंजीकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रम*	
नागरिक शिकायत निगरानी*	कार्यान्वित
कार्मिक प्रबंधन प्रणाली*	
निर्माण योजना अनुमोदन*	
ई-प्रापण	
क्या नागरिक अपने बिल एवं करों का भुगतान सिटीजन फैसिलिटी सेन्टर (सीएफसी) पर कर सकते हैं?#	केवल सीएफसी पर
क्या शहरी स्थानीय निकायों पर भुगतान करने की ऑनलाइन सुविधा है#	नहीं
शहरी स्थानीय निकायों में उपयोग किया जाने वाला ई-मेल सॉफ्टवेयर क्या है#	एनआईसी
क्या शहरी स्थानीय निकाय के कार्यालय लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन)/वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं#	नहीं
क्या आप स्टेट डाटा सेन्टर (एसडीसी) का उपयोग करते हैं?#	नहीं
क्या शहरी स्थानीय निकाय की स्वयं की वेबसाइट है#	हाँ: <a href="http://www.gmcportal.in/">http://www.gmcportal.in/</a>
74 <sup>वें</sup> सीए का कार्यान्वयन#	3 कार्यों को अभी ट्रान्सफर किए जा रहे हैं। ये हैं अग्निशमन सेवाएं, शहरी वानिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का संरक्षण।

नोट: यूएलबी में ई-गवर्नेन्स के मॉड्यूल कार्यान्वित किए

स्रोत: \*सुधार मूल्यांकन रिपोर्ट, जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं संबंधित शहरी स्थानीय निकायों की वेबसाइट

#शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2012 की सूचना एवं सेवाएँ आवश्यकता आकलन (आईएसएनए) अध्ययन

## मान्यता

राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सम्मानों, पुरस्कारों, पायलटों, क्षेत्रीय नेटवर्कों की सूची।	<ul style="list-style-type: none"> <li>आईसीएलईआई के सदस्य</li> </ul>
---	--

## 6. वित्तीय एवं स्वास्थ्य

### वित्तीय

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
बैंकिंग सुविधाओं के उपयोग के साथ घरों का %	54.09	57.21	67.77

वित्तीय स्थिति#		
नगर निगम के आय और व्यय का विवरण (लाख रु. में)	आय	व्यय
2009-10	6931.50	6530.25
2010-11	7239.29	6786.86
2011-12	लागू नहीं	लागू नहीं
नगरीय गरीबों के लिए आरक्षित बजट का प्रतिशत@	लागू नहीं	

स्रोत: मकान, घरेलू सुविधाएं और परिसंपत्तियों की तालिका, भारत की जनगणना, 2011

#शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की 2012 की सूचना एवं सेवाएँ आवश्यकता आकलन (आईएसएनए) अध्ययन

@ जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सुधार मूल्यांकन रिपोर्ट



## पर्यावरण

स्वच्छ भारत रैंकिंग*	लागू नहीं
उपलब्ध शहरों के लिए व्यापक पर्यावरण आकलन#	लागू नहीं

स्रोत: \*प्रेस सूचना ब्यूरो, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2015

#केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, 2009

## 7. क्षमता: टैक रिकार्ड और पहल

जेएनएनयूआरएम परियोजनाएं	स्थिति या टिप्पणी			
बीएसयूपी/आईएचएसडीपी	आईएचएसडीपी योजना के तहत कुल 3 परियोजनाएं (अधोसंरचना के लिए 1 एवं आवास के लिए 2) बीएसयूपी के तहत स्वीकृत हुए जिसमें से 2 परियोजना पूरी हो चुकी हैं। परियोजना की कुल लागत रु. 567.40 करोड़ थी। आवास परियोजना का हिस्सा 99 प्रतिशत (रु. 563.67 करोड़) एवं अधोसंरचना परियोजना का हिस्सा 1 प्रतिशत (रु. 3.73 करोड़) है। आवास पर सभी 2 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। 51 प्रतिशत घरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।			
यूआईजी/यूआईडीएसएसएमटी				
परियोजनाओं की कुल अनुमोदित लागत (लाख रु. में)				
परियोजनाओं का क्षेत्रवार ब्यौरा	क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.	कुल लागत (लाख रु. में)	कुल स्वीकृत परियोजनाओं में क्षेत्र की हिस्सेदारी

केन्द्र द्वारा जारी सहायता का हिस्सा (प्रतिशत)				
पूरा किए हुए कार्य का प्रतिशत (वास्तविक प्रगति)				
उपयोग किया गया वित्त (प्रतिशत)				

स्रोत: [www.jnnurm.nic.in](http://www.jnnurm.nic.in) (नवम्बर, 2015 तक पहुंच)

<b>शहरी विकास मंत्रालय की योजनाओं के साथ एकत्रीकरण</b>	स्थिति, टिप्पणी
विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय)	
अमृत	शहर अमृत मिशन के तहत शामिल है। राज्य वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत की जा चुकी है।
जेएनएनयूआरएम	शहर जेएनएनयूआरएम के घटक तहत कवर था।
एनयूआईएस	
पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी)	

स्रोत: शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार